भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 747

जिसका उत्तर 04 फरवरी, 2026 को दिया जाना है ।

15 माघ, 1947 (शक)

तमिलनाडु में डिजिटल ग्राम प्रायोगिक परियोजना

747. श्री नवसकनी के.:
श्री जी. सेल्वम:
श्री सी. एन. अन्नादुरई:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने रामनाथपुरम, कांचीपुरम और तिरुवन्नामलाई जिलों के चयनित गांवों सहित तमिलनाडु में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास, सौर ऊर्जा संचालित प्रकाश व्यवस्था और वित्तीय समावेशन सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल ग्राम प्रायोगिक परियोजना को लागू किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना के अंतर्गत इन जिलों में शामिल गांवों और प्रदान की गई सेवाओं के स्वरूप का ब्यौरा क्या है और कुल कितनी निधि आवंटित, जारी और उपयोग की गई है;

(ग) तमिलनाडु में, विशेषकर उपरोक्त जिलों में, डिजिटल ग्राम प्रायोगिक परियोजना के प्रभाव का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का प्रायोगिक परियोजना के अनुभव के आधार पर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों, विशेषकर रामनाथपुरम, कांचीपुरम और तिरुवन्नामलाई जिलों, में डिजिटल सशक्तिकरण के लिए इसी तरह की या विस्तारित पहल आरंभ करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे अनुवर्ती कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु अपेक्षित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से **(ङ):** देश भर के 700 गांवों (राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले से एक गांव) में शिक्षा सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, कौशल विकास सेवाएं, सौर ऊर्जा संचालित स्ट्रीट लाइट और वित्तीय समावेशन सेवाएं प्रदान करने के साथ-साथ सरकार से नागरिक सेवाएं और व्यवसाय-से-नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए 'डिजिटल ग्राम पायलट परियोजना' शुरू की गई थी।

तमिलनाडु राज्य में डिजिटल विलेज पायलट परियोजना के तहत कुल **32 गांवों** को शामिल किया गया था।

तमिलनाडु राज्य में रामनाथपुरम, कांचीपुरम और तिरुवन्नामलाई जिलों के अंतर्गत आने वाले गांवों का विवरण इस प्रकार है:

क्रम संख्या	जिले का नाम	उप-जिला/ब्लॉक	ग्राम पंचायत	गांव का नाम
1	रामनाथपुरम	परमाकुडी	वेंधोनी	वेंधोनी
2	तिरुवन्नामलाई	तिरुवन्नामलाई	वेंगिक्कल	वेंगिक्कल
3	कांचीपुरम	कांचीपुरम	कांचीपुरम	किलकाथिरपुर

डिजिटल विलेज पायलट परियोजना को इन जिलों के गांवों सहित अखिल भारतीय आधार पर 62.58 करोड़ रुपये की लागत से लागू किया गया है।
इस परियोजना को 31 मार्च, 2024 से सफलतापूर्वक बंद कर दिया गया है।
उक्त परियोजना के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाएं इस प्रकार हैं:

i. शिक्षा सेवाएं: इस परियोजना के तहत प्रदान किए जाने वाले पाठ्यक्रम- बेसिक कंप्यूटर कोर्स (बीसीसी), कंप्यूटर कॉन्सेप्ट (सीसीसी) पर पाठ्यक्रम, टैली-कौशल प्रमाण पत्र, सूचना प्रौद्योगिकी में बेसिक कोर्स (बीसीआईटी)।
ii. अतिरिक्त शिक्षा: प्रतियोगी परीक्षा प्रशिक्षण, सीएडी (कंप्यूटर एडेड डिजाइन) का मूल
iii. स्वास्थ्य सेवाएं: टेली-स्वास्थ्य और टेली-पशु चिकित्सा परामर्श
iv. वित्तीय समावेशन जागरूकता कार्यक्रम
v. सोलर स्ट्रीट लाइट्स
vi. (क) ऑटोमोटिव तकनीशियन, (ख) हैंडसेट मरम्मत, (ग) फील्ड तकनीशियन - घरेलू उपकरण, (घ) इलेक्ट्रिकल तकनीशियन में कौशल विकास।

उपरोक्त सेवाओं ने लाभार्थियों को कई पहलुओं में लाभान्वित किया है, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

- डिजिटल गांवों में पेश किए जाने वाले विभिन्न शिक्षा पाठ्यक्रमों ने लाभार्थियों को बुनियादी कंप्यूटर कौशल, मौलिक लेखांकन ज्ञान प्राप्त करने और लेखांकन उद्देश्यों के लिए टैली का उपयोग करने में सक्षम बनाया।
- डिजिटल ग्राम पहल के तहत व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से विविध कौशल सेटों में प्रशिक्षित लाभार्थियों ने रोजगार के अवसरों में वृद्धि और उद्यमिता के लिए बढ़ी हुई गुंजाइश का अनुभव किया है।
- डिजिटल गांव में प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं ने विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में काफी सुधार किया है।
- वित्तीय समावेशन जागरूकता कार्यक्रम ने जागरूकता और किफायती वित्तीय उत्पादों और सेवाओं को अपनाने में सुधार किया है।
- सौर ऊर्जा से चलने वाली स्ट्रीट लाइटों की स्थापना ने सार्वजनिक सुरक्षा में सुधार, रात के समय गतिशीलता में वृद्धि और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने में योगदान दिया है।
- डिजिटल गांवों के माध्यम से विभिन्न सरकार-से-नागरिक (जी2सी) और बिजनेस-टू-सिटीजन (बी2सी) सेवाओं की डिलीवरी ने अंतिम मील सेवा वितरण को मजबूत किया है और ग्रामीण नागरिकों के लिए सुविधा को बढ़ाया है।

*****